

संख्या: 2464/14-2-99-911/1992

श्री यशवंत राव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वन अध्यापक-2

विषय:-

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग द्वारा उपग्रह सेवा।

तख्त: दिनांक: 21 जून, 1999

वनमूल्य-सौम्य में रेगुलर भावर कम्पनी को रीसा डिस्पोज़िबल याड के
निर्माण हेतु 61-2348 हेप वनमूमि 10 वर्ष के लिए लीज पर दिया
जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या: मू०अ०-231/14-2-1992-911/
92, दिनांक: 14-12-1992 एवं आपके पत्र संख्या: 1926/11ती-96 [सौम्य], दिनांक:
8-1-1999 के संदर्भ में सूचित है कि श्री राज्यपाल महोदय
रेगुलर भावर कम्पनी को रीसा डिस्पोज़िबल याड के निर्माण हेतु 61-2348 हेप वनमूमि
10 वर्ष के लिए लीज पर देने जाने की स्वीकृति भारत सरकार, प्रवाहण एवं वन
संरक्षण के पत्र संख्या: 8-5-93-संख्या०, दिनांक: 22-2-1999 में प्रदत्त स्वीकृति के
आधार पर उनके द्वारा लगायी गयी शर्तों का समावेश करते हुए निम्न शर्तों पर प्रदान
करो हैं:-

- 1) प्रस्तावित वनमूमि के क्षेत्राधिकार स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- 2) परियोजना के व्यय पर समग्र रूप से वनमूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण कराया जाएगा।
- 3) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी गैर वनमूमि को भारतीय वन अधिनियम-1927 के अन्तर्गत ररक्षित/रक्षित घोषित किया जाएगा।
- 4) परियोजना के व्यय पर लीज क्षेत्र का सीमांकन आरंभिक अवधि के तहत स्थापित बनाकर किया जाएगा। साथ ही एक स्तम्भ के द्वारा स्तम्भ को दूरी और विपरिण अंकित की जाएगी।
- 5) यापक कम्पनी के व्यय पर होने अन्ततः वन क्षेत्र पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण कराया जाएगा।
- 6) वनमूमि पर किया वृक्षों का पालन किया जाना जब आवश्यक हो, तो उचित पर्यवेक्षण के तहत उपग्रह सेवा नियम के माध्यम से ही किया जाएगा।
- 7) यापक कम्पनी द्वारा क्षेत्र के पुनर्वासन हेतु अनुमोदित योजना के अनुसार उपलब्ध वृक्षारोपण कराया जाएगा। प्रस्तावित श्रेष्ठतम तथा होने पर विद्यमान श्रेष्ठतम का पुनर्वासन भी यापक कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

हस्ताक्षरित प्रमाणित

For Hind. Co. Industries Ltd.

(Signature)

Sr. Vice (Legal & Admn.)

- 88-प्रस्ताव में उल्लिखित परिचोपना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए वनभूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- 89-वन क्षेत्र में पाये जाने वाले फ़ोरेस्ट सर्वेक्षण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लगायी जाने वाली सभी बांधकाम कम्पनी को मान्य होगी।
- ✓ 100-प्रस्ताव भूमि का उपयोग केवल कृषि प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- ✓ 111-कम्पनी प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- ✓ 112-कम्पनी के सम्बन्धी अधिकारी, कर्तव्य अथवा जेडर या उक्त व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन या उक्त सम्बन्धी कर्म भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगा। क्षति होने की दशा में प्रभावी वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर कम्पनी द्वारा दिये होंगे।
- 113-कम्पनी को हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वनभूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का मुआवजा किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।
- 114-उक्त वनभूमि कम्पनी के उपयोग में तीन वर्षों के अन्दर तब तक नहीं रहेगी, जब तक कम्पनी को उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। आवश्यकता न रहने पर वन विभाग, उपप्रकारकार को बिना किसी प्रतिकर का मुआवजा किये वापस हो जायेगी।
- ✓ 115-वन विभाग के कर्तव्य/अधिकारी अथवा उनके अधिकारियों को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे, प्रस्ताव वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- 116-प्रस्ताव भूमि हस्तान्तरण के बाद भी पूर्व की भाँति रजिस्ट्रार/आरक्षित वनभूमि नहीं रहेगी।
- ✓ 117-प्रस्ताव वनभूमि का वाणिज्य वापार धर पर खिनाधिकारी से मूल्य निर्दिष्ट करके उक्त मूल्य के बराबर प्री-मियम एवं प्री-मियम का उदा प्रतियोगिता वाणिज्य नीति के तहत कम्पनी को वनभूमि का कब्जा दिया जाएगा।
- ✓ 118-कम्पनी द्वारा उक्त शर्तों एवं तात्कालिक शर्तों को सम्मिलित करके हुए एक पट्टाचिह्न का आरेख प्रस्ताव किया जाएगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरण से विधीयित कराया जाएगा। ऐसे पट्टाचिह्न के विधीयित हेतु निर्धारित विधीयित पुराने कृषि विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रों में जहाँ कृषि क्षेत्रों का वन क्षेत्रों की प्रति पट्टाचिह्न के आरेख के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

..... 3/-

हस्ताक्षरित प्रमाणित

For Hindalco Industries Ltd.

(Signature)

(I.J. Joshi)

Sr. Vice President (Legal & Admin.)

